

एक नजर में ...

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है।

खरीफ की सभी फसलों जैसे सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, धान, मूंगफली और कॉटन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ेगा।

धान का समर्थन मूल्य पहले 1,550 रुपए क्विंटल था, अब इसे 1,750 रुपए क्विंटल किया गया

2012-13 में इसमें 170 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी।

2008-09 में धान पर एमएसपी में 155 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी।

क्या है?

ऐसा न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।

जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।

स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए लागत में डीजल के अलावा खाद-बीज, कर्ज पर ब्याज को शामिल करने को कहा था।

साथ ही किसान का एक दिन का पारिश्रमिक तय कर इसे भी लागत में जोड़ने की सिफारिश की थी। इस हिसाब से लागत के 150 फीसदी तक एमएसपी रखने की सिफारिश की गई थी।

एमएसपी का नया फार्मूला

एमएसपी के निर्धारक कारक

अंतरराष्ट्रीय मूल्य स्थिति।

मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है।

बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है।

इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है।

उत्पाद की लागत क्या है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACPI)

इसके अतिरिक्त गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।

यह आयोग कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।